

प्राथमिकताओं का सटीक निर्धारण*

एस.एस.मूंदड़ा

सबसे पहले मैं सुश्री भट्टाचार्य और भारतीय स्टेट बैंक के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे अति प्रतीक्षित महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन पर मुझे आमंत्रित किया है। आप सुधीजन के समक्ष बात करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

इस सम्मेलन की थीम 'भारत की संवृद्धि की बुनियाद डालना' को लें तो मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसे कई मोर्चे हैं जिनके बारे में हमें आशावादी बने रहने के अनेक कारण हैं जैसे: संवृद्धि, मुद्रास्फीति, जनांकिकी, उद्यमिता, लोकतंत्र, राजनैतिक स्थिरता, नवोन्मेष और स्थापना संबंधी प्रतिबद्धता। यहां बहुत से प्रसिद्ध वक्ता और पेशेवर हैं जिन्हें इन विषयों पर बहुत अच्छी पकड़ और जानकारी है जो इनमें से कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन यह हमेशा उपयोगी होता है कि उस संबंध में बाध्यताओं का भी मूल्यांकन कर लिया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि अत्यधिक आदर्श समाधान पाने के लिए सामूहिक विवेक को लागू किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ मैं कुछ सवाल उठाना चाहता हूँ जो इस सम्मेलन में आगे की जाने वाली चर्चाओं में तथा उसके बाद भी चर्चा का विषय बने रहेंगे। लेकिन, विषय में बदलाव के लिए मैं दबावग्रस्त आस्तियों जैसे विषय पर बोलने से परहेज़ करना चाहूंगा क्योंकि इसपर पहले से काफी बोला जा चुका है।

(ए) बैंकिंग का अर्थशास्त्र

चूंकि यह संगोष्ठी बैंकर्स और अर्थशास्त्रियों दोनों के लिए है इसलिए मैं अपनी बात अर्थशास्त्रियों का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रारंभ करता हूँ।

- आर्थिक संवृद्धि के लिए ऋण आवश्यक ही नहीं संभवतः सबसे महत्वपूर्ण तत्व है।
- क्या ऋण वृद्धि और जीडीपी वृद्धि के बीच कोई ऐसा परस्पर संबंध है जिसे मापा जा सके?

मैं कुछ दिनों से इस प्रश्न का उत्तर तलाश रहा हूँ। इस संबंध

में मुझे कुछ स्पष्टीकरण मिले हैं जो इस प्रकार हैं:

- वित्तीय वर्ष 01-14 तक सांकेतिक जीडीपी की तुलना में औसत ऋण गुणक ऐतिहासिक रूप से 1.6X रहा है। (स्रोत: सीईआईसी, डीबी अनुसंधान)
- एक अन्य मॉडल ऋण वृद्धि को जीडीपी वृद्धि और मुद्रास्फीति के आधार पर निम्नलिखित समीकरण के माध्यम से प्रस्तुत करता है:

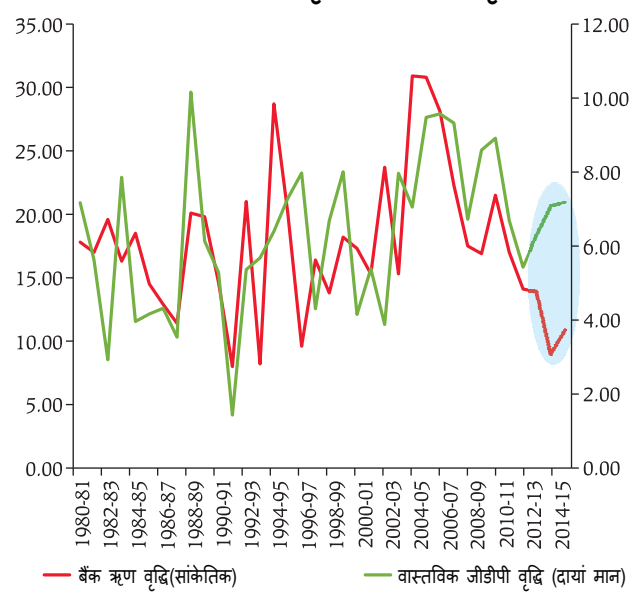
$$\text{ऋण} = 2.36 * \text{जीडीपी} + 0.36 * \text{सीपीआई अथवा ऋण} = 1.93 * \text{जीडीपी} + 0.83 * \text{डब्ल्यूपीआई}$$

(स्रोत : आईसीआईसीआई बैंक अनुसंधान)

दीर्घकाल में वास्तविक जीडीपी वृद्धि और बैंक ऋण वृद्धि के बीच वास्तविक संबंध नीचे चार्ट 1 में दिया गया है।

शायद समय के बीतने के साथ-साथ बैंक ऋण और जीडीपी के बीच का जुड़ाव कमज़ोर पड़ने लगा है क्योंकि बैंक अन्य स्रोतों जैसे कमर्शियल पेपर, बांड्स, आदि के माध्यम से कर्णियों को सुविधा देने लगे हैं और अन्य गैर-बैंक संस्थाओं ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। लेकिन अभी भी 'बैंक' अर्थव्यवस्था को वित्त प्रदान करने का मुख्य स्रोत बने हुए हैं। संभवतः कंपनियों को बैंकों द्वारा दी गई कुल सुविधा और वास्तविक जीडीपी के बीच परस्पर संबंध ज्यादा प्रासंगिक तौर पर हैं बजाय केवल ऋण एवं जीडीपी के बीच के संबंध के।

चार्ट 1: वास्तविक जीडीपी वृद्धि² और ऋण वृद्धि (प्रतिशत)



¹ श्री एस.एस.मूंदड़ा, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 28 सितंबर 2016 को मुंबई में आयोजित तीसरी एसबीआई बैंकिंग और इकानामिक्स महासभा में दिए गए भाषण का मुख्य अंश। संजीव प्रकाश द्वारा दी गई सहायता के लिए बहुत आभार।

² वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर के आंकड़े 1980-1981 से 2011-12 तक 2004-05 के आधार से तथा 2012-13 से 2015-16 तक 2011-12 आधार से लिए गए हैं।

सारणी 1: कुल ऋण प्रसारण - बैंक और गैर-बैंक

(बिलियन रूप में)

निम्नलिखित तिथि को समाप्त	बकाया					गैर-बैंक प्रणाली से ऋण/प्रतिशत हिस्सा	बैंकिंग प्रणाली	कुल
	एनबीएफसी से ऋण	एचएफसी से ऋण	कारपोरेट ऋण लिखत	कमर्शियल पेपर	बाह्य वाणिज्यिक उधार			
मार्च-14	4918.64	4639.42	14673.97	1066.10	7965.52	33263.65	61006.95	94270.6
मार्च-15	6070.79	5623.15	17503.20	2561.20	8337.89	40096.23	66900.45	106996.7
मार्च-16	7469.93	6811.18	20192.96	2602.40	8615.68	45692.15	72732.03	118424.2

स्रोत: पर्यवेक्षी विवरणियां (भारिबैं और अन्य विनियामक)

लेकिन, अर्थव्यवस्था को दिए जाने वाले ऋण का संघटन स्वयं बदलता रहा है जैसाकि ऊपर सारणी 1 में दिया गया है। बैंकिंग प्रणाली में 14 मार्च से 16 मार्च के बीच जहां ऋण 19.22 प्रतिशत बढ़ गया था वहीं उसी अवधि में गैर-बैंक प्रणाली में ऋण 37.4 प्रतिशत बढ़ा था।

तो क्या हम केवल बैंक ऋण के बजाय कुल ऋण आपूर्ति में कोई अंतर-संबंध पाते हैं? (हां/नहीं/हो सकता है)।

जुड़ी हुई कुछ अन्य जटिलताएं

- व्यापार ऋण की महत्वपूर्ण भूमिका है किंतु वह उस प्रकार से हिसाब में नहीं आता है जिस प्रकार से अन्य कारक आते हैं।
- एनबीएफसी/एचएफसी के संबंध में दो बार हिसाब में ले लिया जाता है।
- जीडीपी से जीवीए की ओर चले जाने से विगत की प्रवृत्तियों का विश्लेषण कठिन हो सकता है तथा कम से कम प्रारंभिक वर्षों में नये बेंचमार्क स्थापित होंगे।

मध्यावधि में वास्तविक जीडीपी तथा बैंक ऋण में और अधिक स्थायी मल्टीप्लायर पैदा हो सकता है यदि ये स्थितियां पैदा होती हैं तो:

- बैंक दबावग्रस्त आस्तियों की चिंताओं से बाहर आ जाएं और उनमें जोखिम उठाने की अधिक क्षमता पैदा हो जाए।
- सतत आधार पर निजी निवेश की भावना बेहतर हो जाए(परियोजना वित्त के लिए अधिक मांग पैदा कर दें) और,
- मुद्रास्फीति में गिरावट टिकाऊ तरीके से हो जाए जिससे उधार देने की दरें कम हो जाएं

स्वाभाविक है कि यदि मांग का सही-सही आकलन नहीं किया जाता है तो ऋण देने की रणनीति चाहे जितनी कुशल हो पंगु बनकर रह जाती है। मैं यहां उपस्थित अर्थशास्त्रियों से आग्रह

करता हूँ कि वे इस प्रकार के अंतर-संबंध का मॉडल तैयार करने की संभावनाओं पर कार्य करें।

(बी) ऋण का आपूर्ति पक्ष

मोटे तौर पर स्वीकार किए गए आकलन, ऋण में 12 से 15 प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता बताते हैं जिसकी ज़रूरत मध्यावधि में संवृद्धि को सहारा प्रदान करने के लिए है।

प्रश्न जिनपर विचार करने की आवश्यकता है

- संसाधनों को ऋण की वृद्धि के लिए सपोर्ट करना चाहिए लेकिन आस्ति-देयता असंतुलन को ध्यान में रखते हुए
- कितनी पूंजी चाहिए - कंपोजीशन की मात्रा का ध्यान रहे (सीईटी/टियर I/टियरII)
- किस खंड को कितनी प्राथमिकता दी जाना चाहिए बनाम यह कि बैंक उस प्राथमिकता को कितना अपनाते हैं

i) संसाधन

सकल घरेलू बचत (सारणी 2) तथा बैंक जमा में वृद्धि की प्रवृत्ति (सारणी 3) नीचे दी गई है:

प्रमुख निष्कर्ष

सारणी 2 : सकल बचत

(जीएनडीआई का प्रतिशत)

मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
सकल बचत	33.8	33.0	32.3	32.3
गृहस्थ क्षेत्र	23.0	21.9	20.5	18.7
निवल वित्तीय बचत	7.2	7.2	7.5	7.5
भौतिक आस्तियों में बचत	15.5	14.4	12.7	10.8
मूल्यवान वस्तुओं में बचत	0.4	0.4	0.3	0.3

टिप्पणी: गृहस्थ क्षेत्र की निवल वित्तीय बचत का आकलन वर्ष के दौरान सकल वित्तीय बचत तथा वित्तीय देयताओं के बीच के अंतर से किया जाता है।

स्रोत: सीएसओ, जीएनडीआई: सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय

सारणी 3: बैंक जमा की वृद्धि दर
(प्रतिशत में)

बैंक समूह	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक	सभी बैंक
मार्च-12	13.1	16.8	15.1	13.8
मार्च-13	14.0	18.5	3.9	14.4
मार्च-14	13.1	14.2	22.4	13.7
मार्च-15	8.9	16.5	15.0	10.7
मार्च-16	4.6	17.3	13.2	7.6

- गृहस्थ बचत में गिरावट
- निवल वित्तीय बचत थमी सी रही
- गृहस्थों का कर्ज बढ़ा है

प्रमुख निष्कर्ष

- बैंक जमा की वृद्धि दर अत्यधिक कम हुई है खासतौर से सरकारी क्षेत्र के बैंकों में
- अल्पकाल में, जमा वृद्धि में आए किसी अंतर को बेशी एसएलआर से पूरा किया जा सकता है लेकिन वित्तीय बचत को मध्यावधि से लेकर दीर्घावधि तक सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।
- एएलएम प्रवृत्ति: संस्थागत बचत में धीरे-धीरे कमी ने शायद देयता इयूरेशन को घटा दिया है जबकि आस्ति-इयूरेशन बढ़ रहा है क्योंकि बैंक दीर्घकालिक निधि प्रदान कर रहे हैं।

ii) पूंजी की आवश्यकता

वर्तमान में बैंकिंग प्रणाली में पूंजी की समग्र स्थिति पर्याप्त लग रही है(सारणी 4); लेकिन आगे बढ़कर देखें तो कुछ बैंकों की स्थिति न्यूनतम निर्धारित स्तर पर है। इसका कारण यह है कि कई कंपोनेंट इधर से उधर जा रहे हैं जैसाकि नीचे दिया गया है:

- सामान्य वृद्धि के लिए आरडब्ल्यूए वृद्धि को सपोर्ट करना
- प्रावधान करने की आवश्यकता(जैसाकि नीचे स्पष्ट किया गया है)
- बासेल संरचना(सीसीबी, डी-सिब आदि) - सहमत संरचना के अनुसार
- बृहत एकसपोजर मानदंड - हाल में जारी दिशानिर्देश
- बढ़ा हुआ बाज़ार जोखिम - कारपोरेट बांडों के लिए अधिक ऋण का विस्तार तथा बढ़े हुए डेरिवेटिव पोर्टफोलियो से बाज़ार में जोखिम पूंजी प्रभार अधिक होना
- परिचालनगत अधिक हो जाना - हाल की केवाईसी/एएमएल उल्लंघन की घटनाएं। सयाबर/फिनटेक संबंधी सुरक्षा घटनाओं ने बैंकों के लिए परिचालनगत जोखिम बढ़ा दिए हैं।
- पेशन की फंडिंग - अभी भी अंतर बना रहेगा
- आईएफआरएस - उच्च मूल्य संव्यवहार से बैंकों में पूंजी की आवश्यकता अत्यधिक बढ़ सकती है।

प्रावधानीकरण की आवश्यकता

बैंकिंग प्रणाली में मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार अनर्जक आस्तियों के स्टाक में अवमानक, संदिग्ध तथा हानि वाली अग्रिमों का प्रतिशत क्रमशः 36 प्रतिशत, 59 प्रतिशत और 5 प्रतिशत था(611 हजार करोड़ रुपए)। हालांकि मैं प्रावधानीकरण के आंकड़ों के बारे में अनुमान लगाकर कोई आश्चर्यजनक स्थिति नहीं पैदा करना चाहता क्योंकि इसका स्वरूप बदलते रहने का है, जो भी हो अनर्जक आस्तियां जैसे जैसे लंबी समय की होती जाएंगी और मानक आस्तियों का कुछ प्रतिशत एनपीए श्रेणी में चला जाएगा, तब यह संपूर्ण प्रणाली आने वाले

सारणी 4 : बैंकों में पूंजी पर्याप्तता

बैंक/बैंक समूह का नाम	अवधि	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
सीआरएआर	31-मार्च-15	11.44	15.73	16.81	12.96
	31-मार्च-16	11.82	15.68	17.08	13.32
सीईटी । पूंजी अनुपात	31-मार्च-15	8.26	12.77	15.55	10.01
	31-मार्च-16	8.66	13.11	15.9	10.49
टियर I पूंजी अनुपात	31-मार्च-15	8.73	12.8	15.57	10.33
	31-मार्च-16	9.13	13.16	15.92	10.81
टियर II पूंजी अनुपात	31-मार्च-15	2.72	2.93	1.25	2.64
	31-मार्च-16	2.68	2.52	1.16	2.51

वर्ष में और अधिक बढ़ाते हुए क्रम में प्रावधान करने के बारे में सोचेंगे। यद्यपि बेहतर वसूली एवं वर्तमान एनपीए में बेहतर स्थिति पैदा होने से प्रावधान को वापस किया जा सकता है, उसके बावजूद भी प्रावधान की राशि बहुत अधिक रहेगी। यह इस क्षेत्र के लिए मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार प्रावधान एवं कर के पूर्व सकल आय 2,46,067 करोड़ रुपए होगी। प्रसंगवश, विभिन्न बैंक समूहों के बीच आय में काफी इधर-उधर होने की संभावना है जिसे नीचे सारणी 5 से देखा जा सकता है:

सारणी 5: प्रावधान एवं कर के पूर्व आय (करोड़ रुपए में)				
अवधि	सरकारी क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
31-मार्च-15	139,159	69,850	25,192	234,200
31-मार्च-16	137,151	84,378	24,537	246,067

स्रोत: आसमास विवरणी, भारिबैं.

अन्य प्रभावी कारक जो पूंजी की आवश्यकता पर प्रभाव डाल सकते हैं:

- राजकीय जोखिम एकस्पोजर(राजकीय बांडों पर जोखिम भार)

यह मानक निर्धारण करने वाली निकायों के लिए बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। यहां तक कि यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रतिभूति की बैंक धारिता पर क्रमशः 2 प्रतिशत व 5 प्रतिशत जोखिम भार मान लिया जाए, तो भी बैंकिंग प्रणाली को केवल इसके लिए लगभग 6000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।

जहां हम समझौता के दौरान इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं वहीं राज्य सरकारों को अत्यधिक सावधान रहने की ज़रूरत है कि उनके स्तर पर किसी भी प्रकार की गैरजिम्मेदाराना कार्रवाई हमारे तर्क एवं लिखत जिसे एलसीआर संरचना के अंतर्गत पात्र माना जाएगा, दोनों पर प्रभाव डालेगी।

- जलवायु बदलाव प्रोटोकॉल

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह चर्चाएं चल रही हैं कि जिन उद्योगों से कार्बन निकल रहे हैं उन्हें दंडित किया जाए और बैंकों को ऐसे उद्योगों को दिए गए ऋणों के लिए अतिरिक्त पूंजी रोककर रखना होगा क्योंकि जोखिम भार बढ़ जाएगा।

सीखने की खास-खास बातें:

- प्रत्येक बैंक विभिन्न परिदृश्य के अंतर्गत अपनी पूंजी की आवश्यकताओं का आकलन करे साथ ही विगत की औसत प्रवृत्ति और फिसलन, वसूली एवं उन्नयन पर ध्यान रखे।
- वे पूंजी जुटाने के लिए सावधानी से आदर्श तरीके को भांपें और यह तय करें कि किस सीमा तक इसे जुटाया जाना है।
- इससे वे इस योग्य बन सकें कि अपने कारोबार की बेहतर रणनीति तय कर सकें तथा अपनी जोखिम वहन क्षमता का निर्धारण कर सकें।
- मुझे नहीं लगता कि वर्तमान आईकैप अभ्यास के दौरान पूरी तरह विस्तृत रूप से एवं परिदृश्य-निर्माण के भाग के रूप में इसका अभ्यास किया गया है।

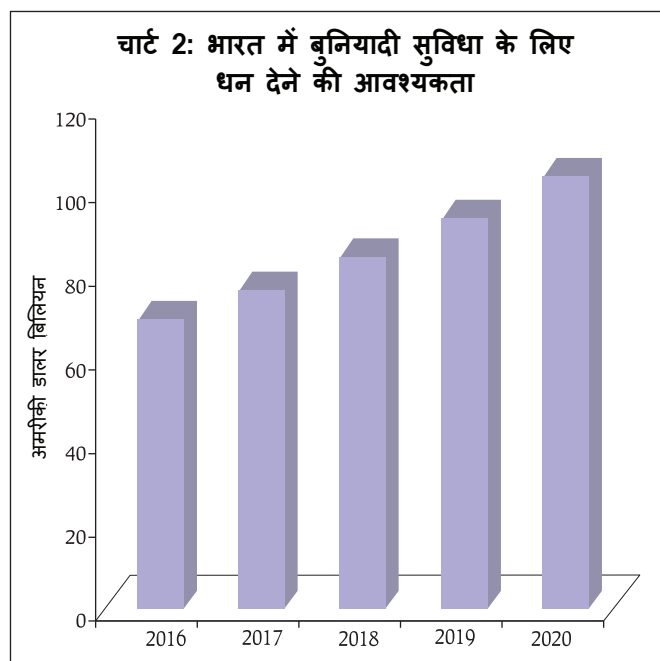
(सी) राष्ट्रीय प्राथमिकताएं

(ए) मूलभूत सुविधाएं

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में यह अनुमान किया गया है कि बुनियादी सुविधाओं में 55.74 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और उसकी 23 प्रतिशत आवश्यकता को बैंकों द्वारा पूरा किया जाएगा। हालांकि योजना समाप्त होने में अभी भी कुछ समय बाकी है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर यह लगता है कि निवेश लक्ष्य एवं बैंक ऋण अनुमान से कहीं कम पड़ेंगे।

ऋण में वर्तमान वृद्धि को देखते हुए और यह कि बैंक देश की बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने के लिए बैंक 23 प्रतिशत को 2016 से 2020 के दरम्यान प्राप्त करने हेतु प्रयास कर रहे हैं (चार्ट 2), उन्हें इस क्षेत्र को अपने कुल वृद्धिशील बैंक ऋण का 17 और 26 प्रतिशत तक उधार देना पड़ेगा। इससे कुछ मुद्दे उठ खड़े हुए हैं:

- आगे चलकर कौन बुनियादी सुविधा का ऋण लेगा? हाल के समय तक कुछ ही प्रवर्तक समूह ने बुनियादी क्षेत्र में हाथ डाला है और अधिकांश 'चोट खाए सेवानिवृत्त' की तरह प्रतीत होते हैं।
- यदि नए खिलाड़ी आ भी जाते हैं तो क्या बैंक (संसाधन एवं पूंजी दोनों तरह से) लैस हैं तथा वर्तमान मॉडल के अंतर्गत उधार देने के इच्छुक होंगे।
- क्या बाहर से आने वाली राशि बुनियादी सुविधाओं के लिए आवश्यक राशि के बड़े हिस्से को पूरा कर पाएगी और यदि कर पाएगी तो क्या आवश्यक उपलब्धकर्ता तैयार हैं।



बी) कृषि

- 2011 कृषि जनगणना के अनुसार,
 - 60 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है
 - इस क्षेत्र में कुल कार्यबल के 55 प्रतिशत को रोजगार मिलता है
 - राष्ट्रीय जीडीपी में कृषि का योगदान 17 प्रतिशत है
 - मामूली सी ज़मीन रखने वाले किसानों की संख्या 1970-71 में 36 मिलियन थी जो 2010-11 में बढ़कर 93 मिलियन हो गई है जिससे पता चलता है ज़मीनों का बंटवारा लगातार हो रहा है जो भूमि में मशीन के इस्तेमाल को हतोत्साहित करता है, श्रमिकों की उत्पादकता कम है और लागत बढ़ गई है।
- कृषि क्षेत्र के लगभग 35 प्रतिशत गृहस्थों के पास 1 एकड़ भूमि है, 35 प्रतिशत के पास 1 से 2.5 एकड़ के बीच ज़मीन है और केवल 30 प्रतिशत गृहस्थों के पास 2.5 एकड़ से अधिक ज़मीनें हैं।
- बड़े किसानों (10 हैक्टर से >) द्वारा लिए जाने वाले उधार का 80 प्रतिशत हिस्सा संस्थागत स्रोतों से आता है, जबकि केवल 15 प्रतिशत भूमिहीन किसानों को औपचारिक स्रोतों से वित्त प्राप्त हो पाता है।

सारणी 6 : बकाया कृषि ऋण

(वास्तविक खातों की संख्या और राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	फसल ऋण		मीयादी ऋण		कुल राशि	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
2014	39049508	397718	11766229	179048	50815737	576766
2015	43209609	471888	11966785	175133	55176394	647021
2016	46854333	542458	11952483	175715	58806816	718173

- पिछले 4 दशकों से अधिक समय से भूमि 140 मिलियन हैक्टर ही बनी हुई है जिसके 50 प्रतिशत हिस्से की ही सिंचाई हो पाती है।
- हालांकि समय बीतने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋण बढ़ते रहे हैं (सारणी 6), कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक ऋण एवं निवेश-ऋण की मात्रा घटती रही है। इस क्षेत्र की ऋण समाहित करने की क्षमता के लिए कोई अन्य अतिरिक्त कारक योगदान ही दे रहा है इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि किस प्रकार से वृद्धिशील रूप से ऋण का इस्तेमाल इस क्षेत्र में किया जाए।

कृषि क्षेत्र से संबंधित कुछ अन्य मुद्दे भी उल्लेखनीय हैं:

- नई पीढ़ी कृषि का कार्य करने में दिलचस्पी नहीं रखती है और शहर की तरफ भाग रही है।
- हालांकि अनेक उपाय किए जा रहे हैं जैसे ग्रामीण सड़क को बेहतर बनाना, ई-कनेक्टिविटी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, पावर कनेक्टिविटी, सिंचाई के लिए जल-निकाय, कृषि बीमा आदि , लेकिन ये वृद्धिशील उपाय देश की कृषि की हालत बदलने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
- प्रयास यह होना चाहिए कि किसी एक-एक स्तर को ऋण देने के बजाय कृषि की समस्त मूल्यवान-श्रृंखला को वित्त प्रदान करने के लिए लक्ष्य किया जाना चाहिए।
- इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने दृष्टिकोणों पर सख्ती से नज़र डालना होगा कि वे अपने स्टाफ को ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात करें। इस समय ग्रामीण शाखाओं में स्टाफ की बहुत सख्त ज़रूरत है जो उनके फोकस किए गए लक्ष्य को प्रभावित कर रहा है।

सी) एमएसएमई

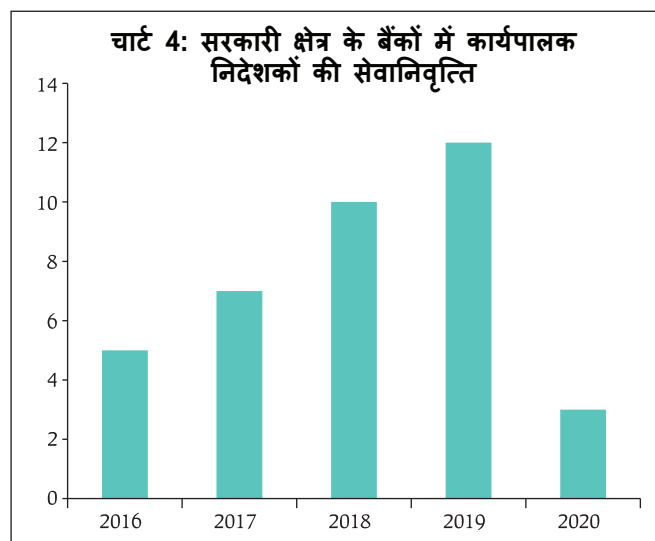
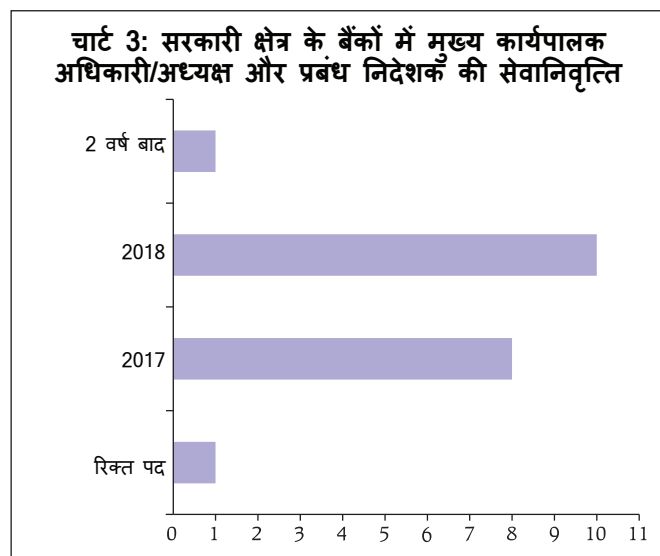
- 12वीं पंचवर्षीय योजना(2012-17) ने भारत में एमएसएमई वित्त क्षेत्र में 56 प्रतिशत के ऋण अंतराल को रेखांकित किया है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो यह 16 ट्रिलियन रुपया होता है जो कुल बैंक ऋण का तकरीबन 25 प्रतिशत है।
- 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार समस्त वाणिज्यिक बैंकों का एमएसएमई क्षेत्र को बकाया ऋण घटता रहा है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के साथ एवं अन्य हितधारकों के साथ मिलकर इस क्षेत्र को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं।
- बैंकों के लिए ज़रूरी है कि वे अच्छी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करें और ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवोन्मेषी ऋण स्कोरिंग करें खासतौर से सूक्ष्म तथा लघु खंड में क्योंकि इसका अधिकांश प्रतिशत औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर है।
- लेकिन इस प्रक्रिया में, बैंकों के लिए आवश्यक है कि इस क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक कर्ज देने के प्रति सावधान रहें।

डी) मानव संसाधन

केवल वित्त प्रदान करने से ही संवृद्धि सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, बैंकिंग अभी भी ड्राइवर रहित कार से बहुत दूर है, इसलिए मानव कारक बहुत ही महत्वपूर्ण है।

(i) सरकारी क्षेत्र के बैंक

नीचे दिए गए चार्ट 3 और 4 में अगले कुछ वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों से सेवानिवृत्त होने वाले शीर्ष प्रबंधन की स्थिति प्रस्तुत करते हैं:



- उप महाप्रबंधक/महाप्रबंधक संवर्ग के 73 प्रतिशत से अधिक स्टाफ 55 वर्ष की आयु से अधिक हैं, जबकि 23 प्रतिशत स्टाफ 50 से 55 वर्ष की बीच हैं।
 - नेतृत्व की यथोचित अवधि महत्वपूर्ण है
 - शीर्ष के कार्यपालकों के स्थान पर नए लोगों को लाने के लिए पाइपलाइन भी कमजोर है और वह कुछ वर्ष बाद ही बेहतर हो पाएगी
- (ii) निजी क्षेत्र के बैंक निचले स्तर पर बहुत ही ज्यादा संघर्षण महसूस कर रहे हैं इसीलिए ग्राहकों से कनेक्ट कम होता जा रहा है और निष्पादन के प्रति अत्यधिक दबाव से गलत-बिक्री की संभावना हो सकती है। इस क्षेत्र पर शीर्ष प्रबंधन को फौरन ध्यान देना होगा।

(ई) समापन विचार

- सायबर जोखिम/ धोखाधड़ी/गलत-बिक्री/बाज़ार के गलत संचालन में यह क्षमता है कि वह वित्तीय संस्था को ज़मीन पर ला दे जैसाकि हाल की घटनाओं से देखा गया है।
- बैंकों को 'मूल्य सहवर्धी' और 'मूल्य आधारित' वित्तपोषण करने की आवश्यकता है।

मैं अपनी बात चीनी कहावत से समाप्त करना चाहता हूँ जिसके अनुसार 'वृक्ष लगाने का सबसे उपयुक्त समय 20 वर्ष पहले था और दूसरा सबसे अच्छा मौका अब है' यदि दूसरे मौके पर यह क्षेत्र वृक्ष लगाने का अवसर नहीं चूकता है तो वह अच्छा निष्पादन कर पाएगा।

धन्यवाद।